RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary 2021; 6(3):84-89
ISSN: 2455-3085 (Online)
https://doi.org/10.31305/rrijm.2021.v06.i03.013

Research Paper

Double Blind Peer Reviewed/Refereed Journal
https://www.rrjournals.com/

नेपाल का राजनैतिक परिवेश एवं विदेश नीति की वर्तमान चुनौतियां

*प्रकाश

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

ABSTRACT

दक्षिण एशिया में नेपाल की अवस्थिति ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय एवं स्वयं को महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक स्थिति प्रदान की है। नेपाल की सीमा रेखा ने दक्षेस के सभी राष्ट्रों के लिए आशाएं एवं वर्चस्व की चुनौती पेश की है, देश के प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी एवं पूँजीगत क्षमता, राजनीतिक व्यवस्था में पुरातन एवं नवीन प्रणाली के मध्य संघर्ष, देश के समृद्ध इतिहास एवं गौरवपूर्ण संस्कृति ने प्राकृतिक रूप से सुन्दर देश वर्तमान समय में सामरिक दृष्टि से वैश्विक पटल पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शुरूआती दौर में राजशाही शासन व्यवस्था की प्रणाली थी लेकिन समय के साथ इसके खिलाफ माओवादियों ने सड़क से संसद तक का सफर तय किया और 2006 में लोकतंत्र की नयी किरण जगी, लेकिन सर्वसम्मति के अभाव में विरोध के स्वर मुखर हुए जिसका दोषारोपण भारत पर आया। नेपाल की परिवर्तित विदेश नीति ने भारत की चिंताओं को नजरअंदाज कर चीन के साथ सामरिक संबंध स्थापित किये जो अविश्वास की भावना पैदा करता है। इस शोध–पत्र का उद्देश्य नव लोकतांत्रिक नेपाल की संतुलित विदेश नीति एवं इसके क्रियान्वन का अध्ययन करना है।

Keywords: *प्राकृतिक संसाधन, पूँजीगत क्षमता, सामरिक दृष्टि, सर्वसम्मति, संतुलित नीति, लोकतंत्र*

Article Publication

Published Online: 15-Mar-2021

***Author's Correspondence**

प्रकाश

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

✉ pprakashp4[at]gmail.com

© 2021The Authors. Published by *Research Review Journals*

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

1. प्रस्तावना

अपनी विदेश नीति के निर्धारण में देश का भौगोलिक आकार, स्थिति एवं भू–भाग में पाये जाने वाले प्राकृतिक संसाधन, वैज्ञानिक प्रगति, पूँजीगत क्षमता के अलावा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी तरफ देश का प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति के साथ–साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक कारक भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। नेपाल की उत्तरी सीमा साम्यवादी देश चीन के साथ एवं दक्षिण की सीमा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत के साथ लगती है। अपनी सामरिक स्थिति के कारण विश्व पटल पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रारम्भिक दौर से ही नेपाल पर राजाओं, सरदारों एवं सामंती वर्गो का शासन रहा है, वास्तविक स्वरूप में नेपाल पर राजशाही शासन तथा सामंती संरचना स्पष्ट रूप से परिलक्षित थी जो प्रशासन के कठोर एवं संकेन्द्रीकृत स्वरूप को धारण किया हुआ था, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने पारिवारिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करना था।[1]

2. राजतंत्र बनाम जन आन्दोलन

राजशाही शासन प्रणाली में राजकुमारों एवं सरदारों के अत्यधिक हस्तक्षेप से राजतंत्र में शिथिलता एवं विकेन्द्रीकरण प्रारम्भ हो गया जिसके परिणामस्वरूप आमजन में पशुपति के अवतार राजा के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न होनी प्रारम्भ हो गयी, जिसका प्रत्यक्ष फायदा साम्यवादी पार्टी सीपीएन (माओवाद) ने उठाया और राजतंत्र के विरूद्ध 1990 में जन आन्दोलन प्रारम्भ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप हजारों आम नागरिकों एवं सुरक्षाकर्मियों को अपनी जान गवानी पड़ी। जन आन्दोलन ने जब विकराल स्वरूप धारण किया तो राजा महेन्द्र ने 1990 में पंचायत शासन प्रणाली में शिथिलता प्रदान करके देश में बहुपार्टी लोकतंत्र का मॉडल अपनाया ताकि आमजन को शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी प्रदान करके जनआन्दोलन को शांत किया जा सके, किंतु माओवादियों के

नेतृत्व में आन्दोलन ने अपनी रफ्तार कई गुना बढ़ा ली थी। इस आन्दोलन से देश में अस्थिरता एवं भय का वातावरण बन गया और राजशाही के उन्मूलन एवं लोकतंत्र की स्थापना की माँग उठने लगी तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार राजशाही पर बढ़ता जा रहा था, इसी क्रम में भारत ने अपने वरिष्ठ राजनयिक डॉ. कर्ण सिंह को नेपाल भेजा ताकि राजतंत्र एवं जनतंत्र के समर्थकों के सुलटारा किया जा सके। 2006 में नेपाल की राजशाही ने अपने समस्त अधिकारों का त्याग कर दिया एवं संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा के गठन करने हेतु ''सेवन पार्टी एलायन्स'' का निर्माण किया गया जिसमें नेपाल के विभिन्न विचारधारा वाले सात राजनैतिक दलों का समावेश था।

3. संविधान निर्माण एवं मधेशी आन्दोलन

नेपाल ने लगभग 7 वर्षों से जारी आंतरिक गतिरोध के बीच 2015 में नये संविधान को प्रख्यापित किया गया जो आजतक का सबसे आधुनिक दस्तावेज माना गया है जिसमें विभिन्न विचारधाराओं को समायोजित करके निम्न प्रावधान किये गयेः–

- राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री के पास कार्यकारी शक्तियाँ होगी।
- केन्द्र एवं प्रांतों में केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारे होगी तथा जिला एवं ग्राम स्तर पर शासन की इकाईयाँ होगी।
- केन्द्र स्तर पर संसद का स्वरूप द्वि–सदनीय और प्रांत में एक सदनीय विधानसभा होगी।
- त्रि–स्तरीय न्यायपालिका का निर्माण किया गया।
- राष्ट्रीय भाषा नेपाली को अपनाया गया है, वहीं स्थानीय एवं जनजातीय भाषाओं को भी मान्यता प्रदान की गई है।
- पर्यावरण संरक्षण के तौर पर गाय को राष्ट्रीय पशु एवं रोडेन्डून को राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया है।
- नेपाल का हिन्दू राष्ट्र का दर्जा समाप्त करके धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया साथ ही प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं को संरक्षण प्रदान किया गया।
- आरक्षण एवं कोटा व्यवस्था के माध्यम से वंचित, पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण किया जायेगा एवं प्रशासन के प्रत्येक पर आरक्षण का प्रावधान किया गया।
- समलैंगिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाला नेपाल विश्व का पहला राष्ट्र बना।

समय एवं परिस्थितियों के आधार पर अगर जरूरत पड़ी तो संविधान संशोधन की लचीली व्यवस्था को अपनाया गया है।

नव अंगीकृत संविधान के लागू होने के साथ ही नेपाल का एक बड़ा वर्ग इसके विरोध में उतर गया तथा पूरे नेपाल में विरोध प्रदर्शन, आगजनी, आर्थिक नाकेबन्दी प्रारम्भ हो गयी। नये संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान थे जो मधेशी एवं थारू समुदाय की आशाओं के विपरित थे।

इन्होंने आरोप लगाया की मधेशी एवं थारू समुदाय नेपाल के तराई क्षेत्र में कुल 27 जिले आतें है जिनमें से 8 जिलो को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया और बाकी 19 जिलों को विद्वेष की भावना से पहाड़ी क्षेत्र के साथ डाल दिया गया जिससे मधेशी समुदाय की जनसंख्या को दो भागों में बाँट दिया गया है, जिसका एकमात्र उद्धेश्य मधेशी समुदाय की ताकत को तोड़ना है। हालांकि आरोप ये भी थे की मधेशी एवं थारू समुदाय को संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, इसलिए किसी भी मधेशी पार्टी ने अंगीकृत संविधान पर अपनी सहमति नहीं दी थी संविधान में निम्न अनुच्छेदों को भेदभाव मूलक बताया गया।

- **अनुच्छेद 63(3)** – भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन।
- **अनुच्छेद 154** – प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा किंतु अंगीकृत संविधान में यह समय सीमा 20 वर्ष है।
- **अनुच्छेद 283** – संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों का प्रावधान।
- नागरिकता संबंधी प्रावधान

एक बात तो तय है कि नेपाल का संविधान प्रजातीय संघर्ष को ओर अधिक बढ़ावा देगा, क्योंकि मुस्लिम, गुरूंग और लिम्बू जनजातिय समुदाय एवं मधेशी–थारू समुदायों के बीच सत्ता प्राप्ति का संघर्ष नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करेगा।

मधेशी समुदाय ने भेदभाव मूलक अनुच्छेदों के विरोध में भारत–नेपाल के बीच आवागमन के मार्ग को अवरूद्ध कर दिया, इस आर्थिक नाकेबन्दी का आरोप नेपाल की सरकार ने भारत पर लगाया और इस मामले को यूएनओ में लेकर गया तथा भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन के साथ पारगमन संधि पर हस्ताक्षर किये, जिसके परिणामस्वरूप चीन से आवश्यक वस्तुओं का आयात शुरू कर

दिया गया। हालांकि कुछ समय पश्चात भारत के हस्तक्षेप से नेपाल ने अपने प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से अनु. 63(3), 154, 283 में बदलाव किया जिसके परिणामस्वरूप मधेश आन्दोलन समाप्त हो गया।[3]

4. चुनाव पूर्व गठबंधन की राजनीति

लोकतांत्रिक तरीके से प्रथम आम चुनावों का आयोजन नवम्बर–दिसम्बर, 2017 को किया गया, इससे पहले जो भी चुनाव आयोजित किये गये वे सभी या तो राजशाही शासन के अधीन या फिर अंतरिम संविधान के तहत हुए। वैसे तो नेपाल के सभी राजनैतिक दल जोड़–तोड़ की गणित राजशाही के समय भी करते रहे है, लेकिन चौकाने वाली बात यह है कि दो विरोधी विचारधारा वाले राजनैतिक दल सत्ता प्राप्ति हेतु चुनाव पूर्व गठबंधन करके सभी राजनैतिक पंडितों को सकते में डाल दिया।

स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम ने इन गठबंधनों की भूमिका तय कर दी थी सभी राजनैतिक दलों ने अपने अनुकूल समीकरण तय करके गठबंधन में शामिल हो गये, इसमें पहला कदम वामपंथी दलों ने रखा जिसमें सीपीएन (यूएमएल) एवं सीपीएन (माओवाद) जो हमेशा से ही घोर विरोधी पार्टियाँ रही है। संसदीय एवं प्रांतीय चुनावों के लिए दोनों दलों ने क्रमशः 60 : 40 में सीटों का बँटवारा किया तथा वामपंथी दलों ने मिलकर एक ही घोषणा पत्र पर सहमत हो गये और अन्य समान विचारधारा वाले छोटे दलों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। वामपंथी दलों ने अपने घोषणा पत्र में नेपाल की राष्ट्रीयता, संम्प्रभुता, पड़ौसी राष्ट्रों के साथ तुलनात्मक संबंध स्थापित करना इत्यादि अवयवों को शामिल किया।[4]

वामपंथी गठबंधन के विरूद्ध नेपाली कांग्रेस ने लोकतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया इसमें छः मधेशी दल भी शामिल थे। इस गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में उदारवादी राजनैतिक मूल्यों की स्थापना, भारत के साथ मजबूत द्वि–पक्षीय संबंध स्थापित करने एवं मधेशी समुदाय की माँगों पर गहनता के साथ विचार करने का वादा किया।

देश के प्रथम आम चुनाव में मुकाबला दो गठबंधनों के बीच था, जिसमें एक तरफ भारत समर्थक उदारवादी दल तथा दूसरी तरफ चीन समर्थक वामपंथी दल शामिल थे। हालांकि इन गठबंधनों का निर्माण चुनाव के पूर्व में हो चुका था, इसलिये इसकों अनुचित नहीं मान सकते किंतु गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों में सामाजिक–आर्थिक तथा विदेश नीति को लेकर गहरा अंतरविरोध था। चुनाव के पश्चात् यह गठबंधन राजैनतिक स्थिरता प्रदान कर पायेगा? इसके बारे में कोई ठोस अनुमान नहीं था।

चुनाव परिणामों को लेकर जैसा विश्लेषकों का अनुमान था उसके अनुसार ही नतीजे सामने आये, वामपंथी गठबंधन को जबरदस्त जनादेश मिला, इससे नवलोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद जरूर जगी थी। इस ऐतिहासिक जीत से वामपंथी गठबंधन द्वारा नेपाल में किया गया प्रयोग पूरा तरह सफल रहा जहाँ पर प्रत्येक मुद्दे पर भारत विरोधी दृष्टिकोण की नीति अपनाई गई, वही भारत समर्थक लोकतांत्रिक गठबंधन को इस चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा इसके पीछे प्रमुख वजह आर्थिक नाकेबन्दी थी, जिसका दोषारोपण वामपंथी गठबंधन ने भारत पर किया गया।

इस निर्णायक जनादेश से नेपाल में पिछले 20 वर्षों से चली जा रही राजनीतिक अस्थिरता थमने के पुख्ता आसार है, इस मजबूत जनादेश से गरीबी एवं प्राकृतिक संकट तथा अस्थिर विदेशी ऋण के जाल में फंसे इस पहाड़ी देश के आर्थिक विकास के लिए एक नयी आशा जगाई है। इन चुनावों के साथ ही नवम्बर, 2006 से प्रारम्भ हुई लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी हो गई।[5]

5. साम्यवादी सरकार की विदेश नीति

वामपंथी सरकार ने एक कार्य सूची का निर्माण किया ताकी आने वाले पाँच वर्षों में राजनैतिक गतिरोध का सामना नहीं करना पड़े, हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी मान रहे है कि वामपंथी गठबंधन शायद ही पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पायेगा, क्योंकि माओवादी प्रमुख प्रचंड के साथ मिलकर गठबंधन धर्म का पालन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन के.पी. ओली ने प्रचंड को नियंत्रित करने के लिए ही अन्य वामपंथी समर्थक राजनीतिक दलों को गठबंधन में शामिल किया था। क्योंकि प्रचंड का राजनीतिक इतिहास ज्यादा भरोसे वाला नहीं रहा है। के.पी. ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने बयान में कहा कि– ''नेपाल अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगा तथा जो नेपाल के हित में अच्छा होगा उसको प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, हमारा प्राथमिक लक्ष्य नेपाल को समृद्ध तथा संम्प्रभु बनाये रखना है''।

अगर नेपाल की विदेश नीति में इतिहास पर प्रकाश डाले तो नेपाल ''सार्क'' का संस्थापक सदस्य रहा है तथा सार्क का मुख्यालय की काठमांडू में स्थित है। नेपाल 1955 में यूएनओ बना तथा समय–समय पर यूएनओ के अनेक मिशन नेपाल में काम कर रहे है। वर्तमान समय में नेपाल बिम्सटेक, डब्ल्यूटीओ का भी सदस्य है जो सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता है। दक्षिण एशिया में नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका दूतावास सबसे पहले लन्दन में स्थापित किया गया इसका मतलब नेपाल औपनिवेशिक काल से ही स्वतंत्र एवं सक्रिय विदेश नीति का पालन करता आया है।

1950 की भारत–नेपाल शांति एवं मैत्री संधि की गई, इस संधि के तहत भारत ने नेपाल को कई मामलों में एकतरफा छूट प्रदान कर रखी है। नेपाल अपने व्यापार–वाणिज्य के लिए बिना किसी शुल्क तथा बाधा के भारतीय बन्दरगाहों का प्रयोग करता आया है। नेपाल का बहुत बड़ा कामगार वर्ग बिना वीजा के भारत में कार्यरत है तथा अधिकांश नेपाली विद्यार्थियों की पहली पसन्द भारतीय संस्थान रहे है जिसमें उच्च शिक्षा, चिकित्सा, प्रबंधन के संस्थान शामिल है। लेकिन माओवादी आन्दोलन के समय से ही इस संधि के पुनर्मूल्यांकन की माँग जोर–शोर से उठने लगी थी।

1954 में जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया तो नेपाल ने चीन का समर्थन किया और दोनों देशों ने सामरिक संधि पर हस्ताक्षर किये जो भारत के लिए एक चुनौती थी। 1990 के जन आन्दोलन में भारत ने माओवादियों के विरूद्ध राजशाही को सामरिक हथियारों की सहायता प्रदान की और साम्यवादी आन्दोलन पर अपनी चिंता जाहिर की थी। 2006 में जब देश में आपातकाल लगा तो भारत ने माना की माओवादी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर आन्दोलन करके, चीन से सहायता प्राप्त करके साम्यवादी शासन स्थापित नहीं कर ले, इसलिए भारत ने सभी नेपाली राजनीतिक दलों से अपील की थी कि सभी समूह एक साथ बैठकर बातचीत के माध्यम भविष्य की रणनीति तैयार करें।[7]

6. साम्यवादी सरकार का भारत के प्रति दृष्टिकोण

माओवादी समूहों ने भारत को हमेशा से ही साम्राज्यवादी एवं शोषणकारी राष्ट्र के रूप में नेपाल की जनता के सामने पेश किया है। संविधान निर्मात्री सभा के दोनों चुनावों में माओवादी पार्टी ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया तथा नेपाल की विदेश नीति को नये सिरे से पुर्नस्थापित करने की घोषणा की थी।

माओवादी हमेशा से ही आरोप लगाते आये है कि भारत, नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है जिससे नेपाली संम्प्रभुता के खिलाफ है। इन सबके पीछे प्रमुख उद्धेश्य भारत को संविधान निर्माण की प्रक्रिया से अलग रखना था ताकि नेपाली कांग्रेस तथा मधेशी समुदाय को राजनीतिक रूप से कमजोर करना था। माओवादी समूहों का मानना था कि भारत नवीन संविधान में हस्तक्षेप करके देश की अपना पुच्छलू राज्य बनाकर रखना चाहता है।

प्रथम आम चुनाव में साम्यवादी एलायन्स ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जो इनके लिए वरदान साबित हुआ, इस चुनाव परिणाम पर भारतीय मीडिया ने इसे भारत विरोधी दृष्टिकोण के रूप में पेश किया गया और चीन समर्थक सरकार कहा गया।

7. साम्यवादी सरकार का चीन के प्रति दृष्टिकोण

साम्यवादियों के अगर पिछले इतिहास पर नज़र डाले तो यह सही बात प्रतीत होती है कि जब भी नेपाल में साम्यवादी सत्ता में आये है तो उनकी पहली पसन्द हमेशा से चीन ही रहा है तथा भारत को नियंत्रित करने के लिए चीन कार्ड का प्रयोग करती है। साम्यवादियों की सरकार बनने के पश्चात नेपाल में चीनी निवेश अचानक बढ़ गया तथा भारत की चिंताओं को नजरअन्दाज करके नेपाल ''वन वेल्ट, वन रोड़'' परियोजना में शामिल हो गया, जो भारत की नेपाल में घटती अहमियत का पता चलता है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वरिष्ठ जानकार प्रो. एस.डी. मुनी ने बताया की ''चीन चाहे कितना भी निवेश कर ले, मगर नेपाल के लोग सचमुच में विकास करना चाहते है तो भारत की मदद अवश्यभावी है''। इस समय साम्यवादी एलायन्स यही चाहेगा की चीन के साथ संबंधों के नाम पर भारत को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया जाय, ताकि नेपाल को भरपूर आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके। अब मधेश आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था, उस समय सीपीएन (माओवाद) के प्रमुख प्रचंड ने कहां कि ''हम भारत के यस मैन नहीं होना चाहते'' इसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारत ने कहा कि ''नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, वह चाहे उसके साथ संबंध स्थापित कर सकता हैं, भारत को इससे एतराज नहीं है, हम अपनी नीति पर कायम है''।[8]

8. वर्तमान में विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां

इस समय साम्यवादी एलायंस के सामने प्रमुख चुनौती भारत से मजबूत द्वि–पक्षीय संबंध स्थापित करके विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं–जैसे महाकाली, कोसी, गंडक, टेकनपुर इत्यादि पर विस्तार से वार्तालाप करके, इनके कार्यन्वहन में आ रही बाधाओं को दूर करना होगा तथा भारत को हमेशा यह ध्यान में रखना होगा की समय पर इन परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाय। भारत–नेपाल के बीच खुली सीमा रेखा होने के कारण इस पर सीमा पहचान की वास्तविक समस्या है, जिसमें काला पानी विवाद को वार्तालाप के माध्यम से सुलझा सबसे बड़ी चुनौती है। सीमा विवाद हमेशा से ही भावनात्मक मुद्दा होता है, इसलिए इस पर दोनों राष्ट्रों को नरम रूख अपनाना होगा।

नेपाल एक भू–आबद्ध देश है, इसलिये साम्यवादी सरकार को लगता है कि केवल एक राष्ट्र पर निर्भरता ठीक नहीं है, इसलिये चीन के साथ वार्तालाप क माध्यम से पारगमन सुविधा प्राप्त की जा सकती है। नेपाल के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा व्यापार असंतुलन का है, इससे देश की भारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हालांकि यह मुद्दा सही अर्थो में देश की अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्भर करता है साम्यवादी सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती व्यापार घाटे को कम करना है, भारत ने व्यापार सरलीकरण एवं उपक्षेत्रीय आवागमन को बढ़ाने के लिए ''बीबीआईएन'' मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को बढ़ावा दिया। चीनी मीडिया भारत–नेपाल के बीच विद्रोह बढ़ाने के लिए तरह–तरह के हथकंडे अपना रहा है ताकि हाइड्रो पॉवर एवं आधारभूत संरचना में भारी चीनी निवेश किया जा सके और भारतीय निवेश को कम किया जा सके। नेपाल की सरकार तथा आम नागरिक इस बात से जरूर परिचित होगें की भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है तथा शांतिपूर्ण स्थायित्व में विश्वास करता है इसलिए भारत किसी के लिए घातक नहीं हो सकता किंतु नेपाली थिंक टैंक की अपनी शंकायें वाजिब है, भारत का पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र भारत के सहयोग से ही अस्तित्व में आया। चीन के साथ सीमा विवाद हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है जिसकी बदौलत 1975 में सिक्किम का विलय भारत में किया गया एवं राजीव गाँधी सरकार ने लिट्टे की समस्या से निपटने के नाम पर श्रीलंका में शांति सेना भेजकर हस्तक्षेप किया गया तथा आंतकवाद के उन्मूलन के नाम पर म्यांमार तथा पाकिस्तान में सैनिक कार्यवाही की गई।[9]

इन सभी कार्यवाहियों से नेपाल को चितिंत होना स्वाभाविक है, इनका मानना है कि भारत का अगला निशाना नेपाल होगा, क्योंकि भारत बार–बार नेपाल पर आरोप लगाता आया है कि नेपाल की भूमि पर भारत विरोधी आंतकी प्रशिक्षण शिविर मौजूद है, जिसका पुख्ता सबूत कंधार विमान कांड जो काठमांडू से ही अपहरण हुआ था। भारत के पूर्वी राज्यों में संचालित उग्रवादी तथा नक्सलवादी संगठनों को आर्थिक एवं सामरिक सहायता नेपाल के रास्ते चीन से प्राप्त होती है, इसकी जानकारी भारतीय खुफिया एजेन्सियाँ, भारत सरकार को समय–समय पर प्रदान करती है। इसलिए दोनों देशों के थिंक टैंक की चिंताऐं वाजिब प्रतीत होती है। हालांकि नेपाल के विदेश नीति निर्माताओं को चीन से नजदीकियों की सीख श्रीलंका एवं मालद्वीप से लेनी चाहिए। जिसमें भारत के विरोध के नाम पर चीन के साथ आर्थिक–व्यापारिक समझौते किये थे किंतु वर्तमान समय में कूटनीतिक ऋण के जाल से इन देशों का निकलना मुश्किल हो गया है, स्थानीय जनता चीनी निवेश का भारी विरोध कर रही है तथा महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर चीन का अधिकार स्थापित हो चुका है। चीन ने ''स्ट्रिग ऑफ पर्ल्स'' की नीति के माध्यम से छोटे द्विपक्षीय देशों में अपने नौसैनिक अड्डों का निर्माण कर लिया गया है तथा इन देशों के बाजार में चीनी सामग्री की भरमार आ गई है, जिसके कारण घरेलू अर्थव्यवस्था धराशाही होने के कगार पर खड़ी है। अगर नेपाल, चीन के आर्थिक चक्रव्यूह में फँस गया तो निकलना मुष्किल हो जायेगा। जिस आर्थिक कुरूतियों के नाम पर माओवादी, राजशाही शासन व्यवस्था को धराशाही करने में सफल रहे थे, वही स्थिति दुबारा न उत्पन्न हो जाय, इसका ख्याल नेपाल के नीति–निर्माताओं को विशेष रूप रखना होगा।[10]

9. निष्कर्ष

नेपाल को अपने विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी आर्थिक नाकेबंदी एवं राजनैतिक अस्थिरता का सामना नहीं करना पड़े। सफल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से सीख लेकर नेपाल अपने मजबूत बहुपक्षीय संबंध स्थापित करने होगे। प्रत्येक वर्ष विदेशी निवेश से संबंधित तथ्यों का आँकलन करना पड़ेगा ताकि निर्माणाधीन आधारभूत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हो सके। नेपाल को विभिन्न देशों के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करके वैश्विक शांति, आतंकवाद उन्मूलन एवं पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका अदा करनी होगी, नेपाल को वर्तमान समय में सुशासन की स्थापना और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुदृढ़ीकरण करके सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। अपनी सांस्कृतिक विरासत तथा आध्यात्मिक विचारधारा का समन्वय करके पर्यटन उद्योग विकसित किया जा सकता है। जो देश को सॉफ्ट विदेश नीति की तरफ अग्रसर करेगा जो विश्व को शांति और अहिंसा का सन्देश देगा, जिसकी वर्तमान परिपेक्ष्य में शक्त आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. बराला, एल.आर., नेपाल : प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस, कोणार्क पब्लिकेशन, दिल्ली, 1993, पृ.सं. 08.
2. उप्रेती, बी.सी.,माओइस्ट इन नेपाल, कालपाज पब्लिकेशन, नई दिल्ली वर्ष 2011, पृ.सं. 13.
3. मुनी, एस.डी., माओइस्ट इन्सर्जेन्सी इन नेपालः चैलेंज एंड रेस्पोन्सज, बिलग्राम पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वर्ष 2005, पृ.सं. 31.
4. उप्रेती, बी.सी., नेपाल ट्राजीशन टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रेट, कालपाज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वर्ष 2010, पृ.सं. 92.

5. अधिकारी, आदित्य, द बुलेट एंड बैलेट द बॉक्स स्टोरी ऑफ नेपाल माओइस्ट रिवोल्यूशन, हिमालय पब्लिकेशन, काठमांडू, वर्ष 2014, पृ. सं. 56.
6. उप्रेती, बी.सी., नेपाल द फ्रेमिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनः हिस्ट्री इस्यु एंड चैलेज, वीआईएफ, नई दिल्ली, वर्ष 2014, पृ.सं. 51.
7. झां, हरिवंश, नेपाल्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशनः एन एनालिसस फ्रांम मधेशी प्रोस्पेक्टिव, आईडीएस, नई दिल्ली, वर्ष 2015, पृ.सं.4.
8. झां, हरिवंश, पोस्ट पोलः चहल–पहल इन नेपाल, ओआरएफ, नई दिल्ली, वर्ष 2017, पृ.सं.01.
9. उप्रेती, बी.सी., पूर्वोत्तर, पृ. सं. 52.
10. सहाय, सी.डी., एंड श्रीवास्तव, मधुमिता, नेपाल्स मार्च ट्वार्डस कॉन्स्टिट्यूशन डिमोक्रेसी, वीआईएफ, नई दिल्ली, वर्ष 2018, पृ.सं. 6.